राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

रोकठोक लेखनी ®

RNI NO. : MAHHIN/2019/77511

खबरें बे-रोकटोक

वर्ष 07 | अंक 44 | मुंबई : बुधवार 09 सितंबर 2026 से 15 सितंबर 2026 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 8 | कीमत : 03 रुपये

चोरी की संपत्ति से नहीं चलने देंगे सरकार!

सिब्बल की धनुष-बाण फ्रीज करने की मांग के समर्थन में उतरे उद्धव ठाकरे...

शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट पर तीखा हमला करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल की दलील का समर्थन किया। सिब्बल ने मांग की थी कि अगर पार्टी की पहचान पर अंतिम फैसले में और देरी होती है, तो अविभाजित पार्टी के चुनाव चिह्न 'धनुष-बाण' को फ्रीज कर दिया जाए।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकरे ने सिब्बल के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि जिन लोगों ने पार्टी, उसका नाम और उसका चुनाव चिह्न 'चुराया' है, उन्हें उस चोरी की संपत्ति का इस्तेमाल करके सत्ता मजबूत करने और गलत तरीके से शासन करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

कानूनी देरी पर सवाल

उन्होंने कहा, इस कानूनी लड़ाई में चार साल बीत चुके हैं। दो बड़े चुनाव, नगर निगम चुनाव और जिला परिषद चुनाव हो चुके हैं, जबकि यह मामला तारीख-दर-तारीख खिंचता जा रहा है। इस देरी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। सत्ता बनाए रखने के लिए चुनाव चिह्न का उनका गलत इस्तेमाल रोका जाना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि नाम और चुनाव चिह्न पर उनकी पार्टी का ही हक है। उन्होंने दोहराया कि मौजूदा शासक शासन चलाने में अक्षम हैं और यह विवाद कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। हमें अपना नाम और चुनाव चिह्न बनाए रखने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी।

चुनाव आयोग पर निशाना

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) पर निशाना साधते हुए उन्होंने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ईसीआई हमारी पार्टी के संविधान की जांच कर रहा है, लेकिन फर्जी राजनीतिक पार्टियों, जैसे नरोदा में एक ही ऑफिस शेयर करने वाली छह पार्टियां, जिनके पास 620 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, की ओर आंखें मूंदे हुए हैं। क्या ईसीआई उनके संविधानों की ऑडिट कर रहा है, या हमें यह मान लेना चाहिए कि आयोग उन चंदे में भागीदार है?

शिंदे के बयान का पलटवार

एकनाथ शिंदे के इस बयान का खंडन करते हुए कि चुनाव चिह्न को फ्रीज करना 'बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को फ्रीज करने' के बराबर है, ठाकरे ने कहा, शिंदे और उनके साथी फ्रीज्ड माइंड वाले लोग हैं। मैं उन्हें गौशाला भेजने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मवेशी भी मानवता के काम आते हैं। इन जड़ बुद्धि वाले चोरों ने 'धनुष-बाण' पर बात करने का नैतिक अधिकार खो दिया है।

10.64 लाख की हाई-क्वालिटी नकली करेंसी बरामद,

दोगुने दाम पर बेचते थे फेक नोट, एक गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 ने जाल बिछाकर 500 रुपये के हाई-क्वालिटी नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस की कार्रवाई में कुल 10 लाख 64 हजार रुपये की नकली भारतीय करेंसी जब्त की गई है। बरामद सभी नोट 500 रुपये के हैं। पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान पहले एक महिला को ट्रैप के जरिए पकड़ा गया। उसके पास से 500 रुपये के कुछ नकली नोट बरामद हुए।

महिला से मिली जानकारी और आगे की जांच के आधार पर पुलिस ने कुर्ला के पास एक पुरुष आरोपी तक पहुंच बनाई, जिसके पास से बड़ी संख्या में और नकली नोट बरामद किए गए। दोनों के बीच लिंक होने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक महिला ने ये नकली नोट इसी पुरुष आरोपी से लिए थे।

10 सितंबर तक आरोपी पुलिस कस्टडी में

इस मामले में पुरुष आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 सितंबर तक पुलिस कस्टडी मिली है। महिला की भूमिका की भी जांच की जा रही है और उसे फिलहाल नोटिस दिए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है।

माहिम डाकघर में तीन दिन से सर्वर बंद, नागरिक परेशान...

मुंबई, माहिम: माहिम पश्चिम के डाकघर में पिछले तीन दिनों से सर्वर बंद होने के कारण स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि लगातार तीन दिनों से तकनीकी समस्या होने के बावजूद भारतीय डाक विभाग की ओर से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। माहिम की शाखा डाकघर लेडी जमशेदजी मार्ग पर विजय सेल्स के सामने, माहिम पश्चिम, मुंबईझ्र४०००१६ स्थित है। यहां आने वाले नागरिकों

का कहना है कि सर्वर बंद होने के कारण डाकघर की आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। लोगों को घंटों इंतजार करने के बाद भी कई बार बिना काम कराए वापस लौटना पड़ रहा है।

स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि दोपहर ढाई बजे के बाद कर्मचारियों द्वारा काम करने से मना किया जाता है। इससे नौकरीपेशा लोगों, बुजुर्गों और दूर से आने वाले नागरिकों को विशेष परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि यदि डाकघर में तकनीकी समस्या है तो इसकी जानकारी नागरिकों को स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

तीन दिन से परेशानी, समाधान का इंतजार

नागरिकों का कहना है कि तीन दिनों से सर्वर की समस्या बनी हुई है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रभावी समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को अपने जरूरी डाक, बचत खाते और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए बार-बार डाकघर जाना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने सवाल उठाया है कि यदि एक शाखा स्थायी रूप से बंद कर दी गई है, तो उसके बाद नागरिकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई।

माहिम प्रधान डाकघर में भी समस्या

माहिम का प्रधान डाकघर टाकंदास कटारिया मार्ग, सिटी लाइट सिनेमा के पास, माहिम पश्चिम, मुंबई-४०००१६ स्थित है। यहां भी नागरिकों को डाक संबंधी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, माहिम क्षेत्र की एक शाखा डाकघर स्थायी रूप से बंद कर दी गई है। इसके कारण आसपास के नागरिकों का भार दूसरी शाखाओं और प्रधान डाकघर पर बढ़ गया है। लेकिन जिन शाखाओं में लोग अपना काम कराने पहुंच रहे हैं, वहां भी तकनीकी और सेवा संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं।

सभी कर्मचारी महिलाएं, फिर भी नागरिकों को राहत नहीं

स्थानीय लोगों के अनुसार, संबंधित डाकघर में सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। नागरिकों का कहना है कि कर्मचारियों के महिला होने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी शिकायत यह है कि लगातार तीन दिनों से चली आ रही तकनीकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और नागरिकों को उचित जानकारी एवं सहायता नहीं मिल पा रही है। लोगों की मांग है कि डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मामले का संज्ञान लें और वास्तविक स्थिति की जांच करें।

भारतीय डाक विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग

माहिम के नागरिकों ने भारतीय डाक विभाग से मांग की है कि–

1. **तीन दिनों से बंद सर्वर की समस्या तत्काल दूर की जाए।**
2. **दोपहर ढाई बजे के बाद काम नहीं करने के आरोप की जांच की जाए।**
3. **स्थायी रूप से बंद शाखा के कारण नागरिकों के लिए उचित वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।**
4. **प्रधान डाकघर और अन्य शाखाओं में पर्याप्त व्यवस्था की जाए।**
5. **तकनीकी समस्या होने पर नागरिकों को स्पष्ट जानकारी दी जाए।**
6. **वरिष्ठ अधिकारी स्वयं माहिम के डाकघरों का निरीक्षण करें।**
7. **नागरिकों की शिकायतों के लिए तत्काल समाधान व्यवस्था बनाई जाए।**
8. **माहिम के नागरिकों का कहना है कि डाकघर आम जनता की आवश्यक सरकारी सेवा है। लगातार तीन दिनों तक सेवा प्रभावित होना गंभीर विषय है। अब लोगों की निगाह भारतीय डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर है कि वे इस समस्या का समाधान कब तक करते हैं।**

लोन चुकाने के बाद दस्तावेज लौटाना बैंक की जिम्मेदारी

मुंबईः बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक ग्राहकों के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि लोन पूरी तरह चुकाए जाने के बाद बैंक के पास जमा प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और उन्हें ग्राहक को वापस करना बैंक की कानूनी जिम्मेदारी है। अदालत ने एक मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मुंबई की एक फर्म के टाइटल डीड्स खो जाने पर दिसंबर 2023 से प्रतिदिन 5,000 रुपये की दर से मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की खंडपीठ नेमेसर्स इन वोग क्रिएशन्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। फर्म की ओर से उसके 78 वर्षीय पार्टनर अचला जोशी ने मामला उठाया था। फर्म ने बैंक से क्रेडिट खाते लेने के लिए वर्ष 1979 में अपनी दो बकाया प्रॉपर्टीज के मूल दस्तावेज एसबीआई की दादर शाखा में जमा किए थे। 1979 में बैंक को सौंपे थे मूल दस्तावेज मामला करीब पांच दशक पुराने बैंकिंग लेनदेन से जुड़ा है। मेसर्स इन वोग क्रिएशन्स ने वर्ष 1979 में बैंक से क्रेडिट सुविधाएं हासिल करने के लिए मुंबई के प्रभादेवी और तालोजा में स्थित दो कमर्शियल प्रॉपर्टीज के मूल टाइटल दस्तावेज बैंक के पास जमा किए थे। ये दस्तावेज एसबीआई की दादर शाखा में रखे गए थे। संपत्ति के मूल टाइटल डीड किसी भी मालिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये उसके मालिकाना अधिकार से संबंधित प्रमुख रिकॉर्ड होते हैं। लोन या क्रेडिट सुविधा पूरी तरह चुकाने के बाद इन दस्तावेजों को वापस पाने का अधिकार ग्राहक को होता है। दस्तावेज नहीं मिलने पर हाई कोर्ट पहुंची फर्म विवाद तब पैदा हुआ जब बैंक के पास जमा किए गए मूल दस्तावेज फर्म को वापस नहीं मिले। इसके बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा। याचिकाकर्ता फर्म का प्रतिनिधित्व उसकी 78 वर्षीय पार्टनर अचला जोशी ने किया। अदालत के सामने मुख्य मुद्दा यह था कि ग्राहक द्वारा बैंक के पास सुरक्षा के तौर पर रखे गए संपत्ति के दस्तावेजों की जिम्मेदारी किसकी है और उनके खो जाने की स्थिति में जवाबदेही कैसे तय की जाएगी।

नागपुर : त्योहारों पर हाई-पावर साउंड सिस्टम और लेजर लाइट पर रोक

नागपुरः आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए नागपुर पुलिस ने शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने हाई-पावर और मॉडिफाइड साउंड सिस्टम, तेज बीम लाइट और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह प्रतिबंध 4 सितंबर से लागू हो गया है और 1 नवंबर की रात 11:59 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनमें तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम और लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आम लोगों को परेशानी के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी खतरे भी पैदा हो सकते हैं।

नागपुर पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। हाई-पावर साउंड सिस्टम पर क्यों लगी रोक पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

इसके अलावा, कई बार मॉडिफाइड साउंड सिस्टम का इस्तेमाल निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज पैदा करने के लिए किया जाता है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ऐसे साउंड सिस्टम के उपयोग पर रोक लगाने का फैसला किया है। लेजर और बीम लाइट पर भी प्रतिबंध आदेश में तेज बीम और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि शक्तिशाली लेजर लाइट कई बार वाहन चालकों और आम लोगों के लिए खतरा बन सकती है। विशेष रूप से रात के समय तेज रोशनी से वाहन चालकों का ध्यान भटक सकता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए पुलिस ने इन पर भी प्रतिबंध लगाया है।

मुंबई : संजय गांधी नेशनल पार्क में पुनर्वास का पहला चरण, 4 हजार लोग होंगे शिफ्ट

मुंबईः गोरेगांव के संजय गांधी नेशनल पार्क में और उसके आस-पास रहने वाले लोगों के पुनर्वास का काम अब तेजी पकड़ेगा। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले चरण में करीब 4,000 लोगों को बसाने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में शिंदे की अध्यक्षता में स'ह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में जरूरी फैसले लिए गए। संजय गांधी नेशनल पार्क में करीब 25,000 लोगों को बसाने का प्रस्ताव है। म्हाडा और एसआरए ने वन विभाग को बताया है कि कल्याण के पास खोनी और पनवेल के पास शिरढोंण में 20,000 लोगों के लिए तैयार घर मौजूद हैं। हालांकि, ये जगहें दूर होने की वजह से स्थानीय लोगों ने वहां जाने का विरोध किया है। हाई कोर्ट के निदेशानुसार पार्क की बाउंड्री तय की जाएगी और एक सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। इसके लिए पहले चरण में 4,000 प्रभावित लोगों को बसाने का फैसला किया गया है।

कल्याण: सन्मान निधि रजिस्ट्रेशन में कल्याण आरटीओ दूसरे नंबर पर

कल्याणः महाराष्ट्र सरकार की 'धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र प्रवासी वाहतूक चालक कल्याण मंडल' की 'सन्मान निधि' योजना के तहत वाहन मालिकों और चालकों के पंजीकरण में कल्याण रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कल्याण आरटीओ ने योजना के तहत पंजीकरण के मामले में पूरे महाराष्ट्र में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल्याण आरटीओ के डिप्टी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आशुतोष बरकुल को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक भी मौजूद रहे। 'सन्मान निधि' योजना का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र से जुड़े पात्र बुजुर्ग सदस्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना की निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले पात्र सदस्यों को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। महाराष्ट्र में दूसरे स्थान पर कल्याण आरटीओ कल्याण आरटीओ ने वाहन मालिकों और चालकों तक योजना की जानकारी पहुंचाने और उनका पंजीकरण कराने में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इसी के परिणामस्वरूप कार्यालय राज्य स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंचा। परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को कल्याणकारी योजना के दायरे में लाने के लिए पंजीकरण महत्वपूर्ण है। योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक तभी पहुंच सकता है, जब उसका पंजीकरण निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा के भीतर पूरा हो। कल्याण आरटीओ की ओर से इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में वाहन मालिक और चालक योजना से जुड़ सके। डिप्टी सीएम शिंदे ने किया सम्मानित इस उपलब्धि को लेकर आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आशुतोष बरकुल को सम्मानित किया।

इस मौके पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की मौजूदगी भी रही। सम्मान के जरिए योजना के क्रियान्वयन और पंजीकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के काम को पहचान दी गई। राज्य स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करना कल्याण आरटीओ के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। बुजुर्ग सदस्यों को मिलेंगे 10 हजार रुपये 'सन्मान निधि' योजना विशेष रूप से परिवहन क्षेत्र के पात्र बुजुर्ग सदस्यों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

मुंबई : गणेश चतुर्थी के दौरान मुंबई मेट्रो लाइन-3 की सेवा रात 12 बजे तक जारी रहेगी

मुंबईः मुंबई के गणेशोत्सव की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और लाखों मुंबईवासियों की भगवाना गणेश में आस्था को ध्यान में रखते हुए मुंबई मेट्रो रेल निगम (एमएमआरसी) ने बड़ा फैसला लिया है। एमएमआरसी ने गणेश भक्तों की यात्रा को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और समय बचाने के लिए मेट्रो लाइन-3 यानी एक्वा लाइन की सेवा 14 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक रात 12 बजे तक जारी रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वर्तमान में, कफ परेड और आरे जेवीएलआर दोनों टर्मिनल स्टेशनों से अंतिम मेट्रो रात 10:30 बजे रवाना होती है। अब, गणेशोत्सव के दौरान इन अंतिम यात्राओं का समय बढ़ाकर रात 12 बजे तक कर दिया गया है। इसलिए, गणेश मंडलों और विभिन्न गणेश मंदिरों में दर्शन के लिए आए श्रद्धालु बिना किसी भीड़भाड़ के उत्सव का आनंद ले सकेंगे और रात में सुरक्षित और सुविधाजनक रूप से घर लौट सकेंगे।

मुंबई में गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह मुंबई के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिद्धिविनायक, दादर, वर्ली, महालक्ष्मी और गोरेगांव जैसे इलाकों में स्थित प्रसिद्ध गणेश मंडलों में दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में, एक्वा लाइन की बढ़ती सेवा मुंबईवासियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी। श्रद्धालु मेट्रो के जरिए यातायात जाम से बचते हुए तेजी से और सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकेंगे। मुंबई में गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह मुंबई के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिद्धिविनायक, दादर, वर्ली, महालक्ष्मी और गोरेगांव जैसे इलाकों में स्थित प्रसिद्ध गणेश मंडलों में दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में, एक्वा लाइन की बढ़ती सेवा मुंबईवासियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी। श्रद्धालु मेट्रो के जरिए यातायात जाम से बचते हुए तेजी से और सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकेंगे।

गणेश भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए एक्वा लाइन मेट्रो में 18 इंच (45 सेमी) तक की गणेश प्रतिमाओं को ले जाने की अनुमति दी गई है। इसलिए, मुंबईवासियों को गणेश जी को घर लाने या विसर्जन के लिए ले जाने का एक अधिक सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन विकल्प मिलेगा। गणेशोत्सव मुंबई की उत्सव परंपरा और सामूहिक आनंद का अभिन्न अंग है। इस त्योहारी मौसम में मुंबईवासियों की यात्रा को सुरक्षित, आसान और अधिक आरामदायक बनाने के लिए, एमएमआरसी यह उन्नत सेवा प्रदान कर रहा है।

भिवंडी: कुत्ते के काटने के बाद 32 लोग पहुंचे अस्पताल, दो बच्चे भर्ती; चार महीने में 3292 मामले

भिवंडी: महाराष्ट्र के भिवंडी में कुत्तों के काटने की घटनाओं ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। रविवार को कामतघर इलाके से करीब 32 लोगों को इलाज के लिए आईजीएम सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया। इनमें दो बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें चोट की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती किया गया। स्थानीय स्तर पर एक ही जानवर द्वारा 32 लोगों पर हमला किए जाने की खबरें सामने आईं, हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

आईजीएम सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डॉ. माधवी पेढारे के अनुसार, दोनों बच्चों को कुत्ते के काटने की 'कैटेगरी 3' श्रेणी की चोट थी। इसी कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। अन्य लोगों को भी उनकी स्थिति के अनुसार आवश्यक चिकित्सा सहायता दी गई। एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के अस्पताल पहुंचने के बाद कामतघर इलाके में कुत्तों के काटने की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ गई। स्थानीय खबरों में दावा किया गया कि एक ही जानवर ने करीब 32 लोगों को निशाना बनाया, लेकिन अस्पताल से उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस दावे की विशेष रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि सभी लोगों को एक ही कुत्ते ने काटा या अलग-अलग घटनाओं के बाद वे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे थे।

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक दो बच्चों को भर्ती करने की जरूरत पड़ी। कुत्ते के काटने के मामलों में घाव की प्रकृति और संपर्क के आधार पर उपचार निर्धारित किया जाता है। गंभीर श्रेणी की चोट में समय पर चिकित्सकीय उपचार बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बच्चों को अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। रविवार की घटना कोई अकेला मामला नहीं है। भिवंडी में पिछले कुछ महीनों से कुत्तों के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नगर निकाय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जुलाई के बीच शहर में कुत्तों के काटने के कुल 3,292 मामले दर्ज किए गए। इन चार महीनों में सबसे ज्यादा मामले अप्रैल में सामने आए थे। इन आंकड़ों ने शहर में आवारा कुत्तों और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंता को बढ़ा दिया है। औसत निकाला जाए तो अप्रैल से जुलाई के बीच हर महीने 800 से अधिक कुत्ते के काटने के मामले दर्ज हुए। इतनी बड़ी संख्या स्थानीय प्रशासन के लिए भी चुनौती पेश करती है।

अस्पताल में बवाल का आरोप शिवसेना के 17 लोगों पर केस

पालघर: महाराष्ट्र के पालघर में दही-हंडी समारोह के बाद एक निजी अस्पताल में देर रात हुई कथित झड़प का मामला सामने आया है। रिलीफ हॉस्पिटल की शिकायत के आधार पर शिवसेना के 17 पदाधिकारियों और समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि पार्टी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में प्रवेश कर एक महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी की, तोड़फोड़ करने की धमकी दी और घायल गोविंदाओं के इलाज तथा डिस्चार्ज को लेकर हुए विवाद के दौरान एक स्टाफ सदस्य के साथ मारपीट की।

मामला 5 सितंबर को आयोजित दही-हंडी कार्यक्रम के बाद का बताया जा रहा है। पालघर-मनोर हाईवे स्थित शिवाजी चौक पर दही-हंडी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मानव पिरामिड बनाते समय गोविंदा मंडली के कुछ सदस्य घायल हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रिलीफ हॉस्पिटल ले जाया गया।

अस्पताल में कुल सात घायलों का इलाज किए जाने की जानकारी सामने आई है। घायलों की स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों का सीटी स्कैन और एक्स-रे भी कराया गया। शुरूआत में घायलों के उपचार की प्रक्रिया सामान्य रूप से चली, लेकिन बाद में इलाज के भुगतान और मरीजों को डिस्चार्ज किए जाने को लेकर विवाद पैदा होने का आरोप है। जानकारी के अनुसार अस्पताल की ओर से इलाज के लिए कुल 19,866 रुपये के भुगतान की मांग की गई थी। आयोजकों की तरफ से 10 हजार रुपये जमा किए गए। बताया गया कि बाकी रकम के भुगतान को लेकर गोविंदा मंडली के सदस्यों ने अस्पताल कर्मचारियों से कहा कि शेष राशि शिवसेना के जिला प्रमुख की ओर से दी जाएगी। इसी भुगतान को लेकर बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने की बात कही जा रही है।

अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि बाद में शिवसेना से जुड़े कई पदाधिकारी और समर्थक अस्पताल पहुंचे। यहां घायल गोविंदाओं के इलाज और उन्हें डिस्चार्ज करने के मुद्दे पर अस्पताल कर्मचारियों के साथ बहस हुई। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद एक स्टाफ सदस्य के साथ मारपीट की गई। अस्पताल ने अपनी शिकायत में एक महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी किए जाने का भी आरोप लगाया है।

मुंबई: सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत, धुले में दो वाहन टकराए

मुंबई: धुले जिले के पिंपलनेर में स्थित कवाथे गांव के पास रविवार शाम को एक ट्रक और स्कूटी के बीच हुई टक्कर में पति-पत्नी की मौत हो गई । इस घटना की गहन छानबीन साक्री पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है। इस घटना की छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना में मृतकों की पहचान राजेंद्र महारू नेरकर (66) और उनकी पत्नी रेखा राजेंद्र नेरकर (59) के रूप में हुई है। दोनों दहीवेल से साक्री की ओर स्कूटी से जा रहे थे। इसी दौरान कवाथे गांव के पास होटल ताज के सामने आयशर ट्रक ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में पति-पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक तुरंत मौके पर पहुंचे और निजी एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को साक्री ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया। लेकिन अस्पताल में डॉक्टर डॉ. मुकेश मोरे ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है।

मुंबई: मुंबई एयर कार्गो पर डीआरआई का शिकंजा चीनी नेटवर्क से जुड़े दो लोग गिरफ्तार...

मुंबई: एजेंसी ने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) की मुंबई जोनल यूनिट ने कथित तौर पर चीनी नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे सोने की तस्करी के एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया और लगभग 1.10 करोड़ रुपये मूल्य का 691.870 ग्राम 24-कैरेट सोना जब्त किया। डीआरआई के अनुसार, यह सोना एक ट्रेडमिल की मोटर के अंदर छिपाकर रखा गया था और इसे हांगकांग से मुंबई के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में मंगाई गई एक खेप से बरामद किया गया। एजेंसी के मुताबिक, कस्टम्स एक्ट, 1962 के प्रावधानों के तहत दो लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें एक चीनी नागरिक और आयात करने वाली फर्म का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति शामिल है। जब्ती के बाद, डीआरआई की टीमों ने जांच के हिस्से के तौर पर मुंबई, चेन्नई, तिरुवल्लुर और चेंगलपट्टू में कई जगहों पर तलाशी ली।

जांच से पता चला कि चीनी नागरिकों ने अपने भारतीय साथियों के साथ मिलकर वैध व्यावसायिक आयात के जरिए सोने की तस्करी करने का एक तरीका अपनाया था।

मुंबई: आरसीएफएल मामले में सीबीआई की कार्रवाई तेज, तीन बड़े अधिकारियों समेत 17 पर आरोप

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को मुंबई में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) मामले में पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। सोमवार को सीबीआई ने बताया कि यह चार्जशीट 17 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई है, जिनमें रिलायंस एडीए ग्रुप के तीन अधिकारी - अमिताभ झुनझुनवाला (ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर, रिलायंस एडीए ग्रुप), अमित बापना (सीएफओ, आरसीएल) और रमेश शेनॉय (कंपनी सेक्रेटरी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) शामिल हैं। इसके साथ ही आठ कंपनियां - रिलायंस पावर लिमिटेड, बिग फ्लिक्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, कुंजबिहारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस वेंचर एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़े छह बैंक अधिकारी भी शामिल हैं।

आरोपियों पर आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश, आपराधिक गबन और धोखाधड़ी के अपराधों के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं। अब तक की जांच से पता चला है कि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा लिए गए कर्ज की रकम को बिचौलियों और माध्यम कंपनियों के जरिए रिलायंस एडीए ग्रुप की विभिन्न कंपनियों में डायवर्ट किया गया। ऐसा कर्ज लेने की शर्तों और नियमों का उल्लंघन करके किया गया, जिससे कर्ज देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गलत तरीके से नुकसान हुआ और आरोपियों तथा संबंधित कंपनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचा।

सीबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कंसोर्टियम (संघ) के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से मिली शिकायतों के आधार पर यह मामला दर्ज किया था। सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य कर्जदाताओं को हुआ कुल नुकसान लगभग 9,280 करोड़ रुपए है। इस मामले में पहली चार्जशीट 7 जुलाई 2026 को सात आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई थी।

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

मौत की इमारतों की राजधानी...

दिल्ली देश की राजधानी है अथवा मौत की इमारतों का महानगर है! यह इसलिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि हाल ही में मालवीय नगर के एक 'अवैधह्ण, संकरे कथित होटल में अग्निकांड हुआ, जिसमें 22 जिंदगियां भस्म होकर राख बन गईं। कभी राजेन्द्र नगर में बारिश का पानी भर जाता है, उसमें करंट भी प्रवाहित होने लगता है, नतीजतन आधा दर्जन युवा छात्र अचानक लाश बन जाते हैं। वे आईएएस बनने का सपना लिए पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मौत ने सब कुछ छीन लिया। कभी लक्ष्मीनगर में हादसा हुआ और फिर युवा जिंदगियों पर विराम लग गया। इसी जुलाई में ही रोहिणी में इमारत गिरी, साकेत और करोल बाग में हादसे हुए। मुस्तफाबाद में 11 मौतें इससे पहले हो चुकी थीं। ये हादसे, मौतें नहीं, बल्कि हत्याएं हैं, क्योंकि बचने के बंदोबस्त 'शून्य'थे। और अब संभ्रांत कॉलोनी मोतीबाग के पास सत्य निकेतन में भी एक 5-मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। रविवार रात तक 5 मौतों की पुष्टि की जा चुकी थी। तीन छात्र अस्पताल में जिंदगी-मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मौतों की संख्या अधिक भी हो सकती है, क्योंकि 25-30 छात्रों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है।

इन तमाम इमारतों में एक तथ्य साझा है कि सभी 'अवैध'थीं। न अग्निशमन विभाग का एनओसी, न नगर निगम का एनओसी, स्वीकृत मंजिलों से अधिक मंजिलों का निर्माण और कई इमारतें तो सालों पुरानी थीं, जिनका रखरखाव भी नहीं किया गया था। सत्य निकेतन वाली इमारत भी 36 साल पुरानी बताई गई है। उस पर विभाग ने सील लगा दी थी, लेकिन फिर न जाने कैसे, वह सील भी खुल गई और यह हत्याकांड हो गया। इस इमारत की तीन मंजिलें 'अवैध'थीं, क्योंकि उसे भूतल और पहली मंजिल बनाने की ही अनुमति दी गई थी, लेकिन भूतल के ऊपर भी चार मंजिलों का निर्माण कर लिया गया। दिल्ली नगर निगम के एक पूर्व चेयरमैन और फायर ब्रिगेड के पूर्व निदेशक ने चौंका देने वाला खुलासा किया है कि दिल्ली में करीब 75 लाख इमारतें हैं। उनमें से करीब 1.75 लाख इमारतों के नक्शे पास हैं। शेष सभी इमारतें अवैध और अतिक्रमण की हैं। देश की राजधानी में 1731 अनधिकृत कॉलोनियां हैं। उनमें से 1511 को अधिकृत, नियमित करने के मद्देनजर पीएम-उदय योजना के तहत रखा गया है। एक पुख्ता वोट बैंक की तैयारी... लेकिन यह कितना भयावह यथार्थ है!

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK
LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On
YouTube
LIKE
SHARE
COMMENT
SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

पालघरः अस्पताल में बवाल का आरोप शिवसेना के 17 लोगों पर केस

पालघरः महाराष्ट्र के पालघर में दही-हंडी समारोह के बाद एक निजी अस्पताल में देर रात हुई कथित झड़प का मामला सामने आया है। रिलीफ हॉस्पिटल की शिकायत के आधार पर शिवसेना के 17 पदाधिकारियों और समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि पार्टी से जुड़े नेताओं और कार्यकताओं ने अस्पताल में प्रवेश कर एक महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी की, तोड़फोड़ करने की धमकी दी और घायल गोविंदाओं के इलाज तथा डिस्चार्ज को लेकर हुए विवाद के दौरान एक स्टाफ सदस्य के साथ मारपीट की।

मामला 5 सितंबर को आयोजित दही-हंडी कार्यक्रम के बाद का बताया जा रहा है। पालघर-मनोर हाईवे स्थित शिवाजी चौक पर दही-हंडी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मानव पिरामिड बनाते समय गोविंदा मंडली के कुछ सदस्य घायल हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रिलीफ हॉस्पिटल ले जाया गया।

अस्पताल में कुल सात घायलों का इलाज किए जाने की जानकारी सामने आई है। घायलों की स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों का सीटी स्कैन और एक्स-रे भी कराया गया। शुरूआत में घायलों के उपचार की प्रक्रिया सामान्य रूप से चली, लेकिन बाद में इलाज के भुगतान और मरीजों को डिस्चार्ज किए जाने को लेकर विवाद पैदा होने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार अस्पताल की ओर से इलाज के लिए कुल 19,866 रुपये के भुगतान की मांग की गई थी। आयोजकों की तरफ से 10 हजार रुपये जमा किए गए। बताया गया कि बाकी रकम के भुगतान को लेकर गोविंदा मंडली के सदस्यों ने अस्पताल कर्मचारियों से कहा कि शेष राशि शिवसेना के जिला प्रमुख की ओर से दी जाएगी।

इसी भुगतान को लेकर बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने की बात कही जा रही है। अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि बाद में शिवसेना से जुड़े कई पदाधिकारी और समर्थक अस्पताल पहुंचे। यहां घायल गोविंदाओं के इलाज और उन्हें डिस्चार्ज करने के मुद्दे पर अस्पताल कर्मचारियों के साथ बहस हुई। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद एक स्टाफ सदस्य के साथ मारपीट की गई। अस्पताल ने अपनी शिकायत में एक महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी किए जाने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा अस्पताल में तोड़फोड़ करने की धमकी दिए जाने की बात कही गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिवसेना के 17 पदाधिकारियों और समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर में कई स्थानीय वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के नाम शामिल होने की बात सामने आई है। इनमें शिवसेना के पालघर जिला प्रमुख कुंदन सांखे, शहर प्रमुख राहुल घरात और विधायक राजेंद्र गावित के बेटे रोहित गावित समेत पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकताओं के नाम बताए गए हैं। हालांकि एफआईआर में नाम शामिल होने का अर्थ आरोप सिद्ध होना नहीं है। मामले में पुलिस जांच के बाद ही घटनाक्रम और संबंधित लोगों की भूमिका स्पष्ट होगी। पूरे विवाद की शुरूआत दही-हंडी के दौरान घायल हुए गोविंदाओं के उपचार से हुई बताई जा रही है। दही-हंडी कार्यक्रमों में मानव पिरामिड बनाने के दौरान प्रतिभागियों के गिरकर घायल होने का जोखिम रहता है।

मुंबईः स्वास्थ्य विभाग में ग्रेड के आधार पर तय होगी अधिकारियों की जिम्मेदारी

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उनके काम की पहचान, मेरिट के आधार पर की जाएगी। उनके काम का हर साल लेखा-जोखा किया जाएगा और उसी आधार पर उनके साल के काम का ग्रेड तय करके उनकी प्राथमिकता के साथ जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह फैसला स्वास्थ्य विभाग ने लिया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर के अनुसार परफॉर्मेंस-बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कल्चर बनाने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। जिला सर्जन और जिला हेल्थ ऑफिसर कैडर के अधिकारियों का हर साल ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन किया जाएगा। उनके ग्रेड पिछले तीन वर्षों की परफॉर्मेंस के आधार पर तय किए जाएंगे। इस ग्रेड का इस्तेमाल जिम्मेदारियां बांटने, अगले तीन वर्षों के लिए काम की योजना बनाने और भविष्य की नियुक्तियों के लिए किया जाएगा। इस निर्णय से सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठता के साथ-साथ असल परफॉर्मेंस, नेतृत्व कौशल, मरीजों की देखभाल, वित्तीय अनुशासन, मानव संशाधन प्रबंधन और योजनाओं को असरदार तरीके से लागू करने को अहमियत मिलेगी। बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों को उनकी काबिलियत के हिसाब से आगे मौके देने का सिस्टम बनाया जाएगा। इससे अधिकारियों का हौसला बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2026 को कम से कम तीन साल की सेवा पूरी करने वाले संबंधित अधिकारियों के काम की जानकारी अपडेट की जाएगी और उनकी रेटिंग की जाएगी। तीन साल 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान पोस्ट पर किए गए काम को देखते हुए कुल 100 अंक का मूल्यांकन किया जाएगा। इस रेटिंग के हिसाब से अधिकारियों को चार कैटेगरी ए बी सी और डी में बांटा जाएगा। यह प्रक्रिया हर साल लागू की जाएगी।

सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी... दो आरोपित पुलिस की गिरफ्त में

मुंबईः ओशिवारा पुलिस स्टेशन की टीम ने सोशल मीडिया पर फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाकर लोगों से ठगी करने वाले दो आरोपितों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपितों पर एक महिला को कम रकम के बदले भारी रिटर्न का लालच देकर कुल 73,521 रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले की गहन छानबीन जारी है। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि ओशिवारा की रहने वाली महिला को फेसबुक पर 'विझार्ड ट्रेडर्स ७' नाम का एक पेज मिला था। इस पेज पर एक निवेश योजना का विज्ञापन किया गया था, जिसमें 99 रुपये के भुगतान पर 9,999 रुपये का रिटर्न देने का दावा किया गया था। महिला ने विज्ञापन में दिए गए लिंक पर क्लिक किया, जिसके बाद उसे एक इंस्टेंट मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप के जरिए एक अज्ञात व्यक्ति से संपर्क करने के लिए कहा गया। आरोपित ने उसे कथित निवेश योजना के बारे में जानकारी दी और पैसे लगाने के लिए राजी किया। महिला ने शुरूआत में 99 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इसके बाद आरोपितों ने उससे लगातार संपर्क कर अलग-अलग कारणों से कई और भुगतान करने को कहा।

पुलिस के अनुसार, महिला ने रात से लेकर सुबह करीब 3.30 बजे तक 22 बार पैसे ट्रांसफर किए, जिससे उसे कुल 73,521 रुपये का नुकसान हुआ। इसके बाद महिला ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाया। शिकायत मिलने के बाद ओशिवारा पुलिस की साइबर टीम ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने लेनदेन से जुड़े डिजिटल और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के आधार पर सोशल मीडिया पेज संचालित करने वाले संदिग्धों को राजस्थान में ट्रैक किया गया। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम दौसा और जयपुर पहुंची। पुलिस टीम ने करीब चार दिनों तक आरोपितों की तलाश की, क्योंकि वे लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे।

संक्षिप्त समाचार

गरीब छात्रों के सपनों को पंख लगा रहा 'रफीक सर' का निःशुल्क अभियान

प्रयागराज। आधुनिक तकनीकी दौर में जहां शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, वहीं कुछ शिक्षक आज भी शिक्षा को सेवा का माध्यम मानकर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के सपनों को पूरा करने में जुटे हैं। ऐसे ही शिक्षकों में माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्रयागराज के पीईएस अधिकारी मोहम्मद रफीक का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के पूर्व छात्र मोहम्मद रफीक ने कोविड काल वर्ष 2020 में प्रतियोगी छात्रों के लिए 'टारगेट पीसीएस 2026 विद रफीक' नाम से व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था। वर्तमान में इस ग्रुप से करीब 438 प्रतियोगी छात्र जुड़े हुए हैं। पीसीएस के साथ आरओ/एआरओ एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी इसका लाभ उठा रहे हैं।ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि छात्रों को निःशुल्क अध्ययन सामग्री और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। रफीक सर स्वयं ग्रुप पर सक्रिय रहकर करंट अफेयर्स, विषयवार नोट्स, पत्र-पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र उपलब्ध कराते हैं। छात्रों के सवालों और परीक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी समय-समय पर किया जाता है। इस पहल का असर छात्रों की सफलता में भी दिखाई दे रहा है। ग्रुप से जुड़े 20 से अधिक अभ्यर्थी पीसीएस तथा लगभग इतने ही अभ्यर्थी आरओ/एआरओ परीक्षा में सफलता हासिल कर चुके हैं।??

रेलवे ट्रैक पार करते 8 महीने में 1,070 गिरफ्तार

प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने गैरकानूनी तरीके से पटरियां पार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। इस साल जनवरी से 31 अगस्त के बीच चलाए गए विशेष अभियान में कुल 1,070 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार ट्रैक पार करते पकड़े जाने पर मौके पर ही 500 रुपये का जुर्माना लिया जा रहा है। अगर कोई जुर्माना नहीं भरता है, तो मामला कोर्ट भेजा जाता है। वहां रेलवे कानून के तहत 3 महीने तक की जेल या 5,000 रुपये तक का जुर्माना (या दोनों) हो सकता है। आरपीएफ के आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां बड़े और व्यस्त स्टेशनों पर हुई हैं। इनमें प्रयागराज जंक्शन और चुनार प्रमुख हैं। प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां प्रयागराज जंक्शन पर 124, चुनार में 119, कानपुर सेंट्रल में 112, नैनी में 88 और प्रयागराज छिवकी व फतेहपुर में 75-75 हुई हैं। इसके अलावा, अलीगढ़, कानपुर अनवरगंज, फफूंद, टूंडला, पनकी और फिरोजाबाद जैसे अन्य स्टेशनों पर भी लगातार कार्रवाई की गई। महीने के हिसाब से देखें तो मार्च में 259 और मई में 226 लोग ट्रैक पार करते हुए पकड़े गए, जो सबसे ज्यादा संख्या है। उन्होंने बताया कि लोग कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं। इससे न केवल खतरनाक हादसे होते हैं, बल्कि ट्रेनों के समय पर चलने में भी रुकावट आती है।

फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव, पिता ने लगाया हत्या का आरोप

प्रयागराज। मेजा थाना क्षेत्र में एनटीपीसी रेलवे लाइन के पास शुक्रवार सुबह एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। शव जंगल में एक नीम के पेड़ पर लटका था। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पिता ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता का कहना है कि मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता। उसकी हत्या की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू निषाद गुरुवार शाम करीब चार बजे भैंस चराने घर से निकला था। बताया गया कि उसके साथ आशू निषाद भी दुकान की तरफ गया था। इसके बाद सोनू घर नहीं लौटा। परिजन और ग्रामीण उसे ढूंढते रहे। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे गांव के सामने जंगल में एनटीपीसी रेलवे लाइन के पास नीम के पेड़ पर सोनू का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मेजा थाना प्रभारी नितेंद्र शुक्ला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस घटना से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक के परिजनों का आरोप लगाया कि सोनू की हत्या की गई है। परिजनों ने पुलिस से घटना की जांच कर सच्चाई का पता लगाने की मांग की है। युवक की मौत के असली कारणों का पता पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चलेगा।??

यूपी में बिजली चोरी पर शिकंजा, हाई लॉस क्लस्टर मॉडल से होगी वसूली...

उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने और बिजली वितरण में होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयासों का असर आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है. वर्ष 2020-21 में 20.63 प्रतिशत रही वितरण हानि वर्ष 2025-26 में घटकर 13.04 प्रतिशत रह गई. इसी अवधि में एटीएंडसी हानि भी 31.19 प्रतिशत से घटकर 17.83 प्रतिशत पर आ गई. कृषि फीडरों को छोड़कर प्रदेश में फीडरों की संख्या 18,351 से बढ़कर 21,463 हो गई है. इनमें लाभकारी फीडरों की संख्या 5,772 से बढ़कर 8,104 पहुंच गई. इसमें 2,332 अतिरिक्त फीडर लाभकारी श्रेणी में आए हैं.

लाभकारी फीडरों की हिस्सेदारी भी 31 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई है. डिस्कॉमवार प्रदर्शन में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम 53 प्रतिशत लाभकारी फीडरों के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर रहा. केस्को 39 प्रतिशत, दक्षिणांचल और मध्यांचल 37-37 प्रतिशत तथा पूर्वांचल 22 प्रतिशत पर रहा. ये आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार के कार्यकाल में बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक कुशल, जवाबदेह और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार सुधार हुआ है. योगी सरकार के नेतृत्व में बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए लागू हाई लॉस क्लस्टर मॉडल के तहत प्रदेश में 703 क्लस्टर, 1703 फीडर, 42.21 लाख उपभोक्ता और 76,839 वितरण ट्रांसफार्मरों को कवर किया गया. यह कुल उपभोक्ताओं का करीब 11 प्रतिशत है. अभियान के तहत 654 करोड़ 31 लाख रुपये की बकाया वसूली की गई है, जबकि 1,01,548 नए विद्युत संयोजन जारी किए गए हैं. दक्षिणांचल डिस्कॉम में भी सुधार उल्लेखनीय रहा. यहां वितरण हानि 25.64 प्रतिशत से घटकर 14.78 प्रतिशत और एटीएंडसी हानि 31.03 प्रतिशत से घटकर 19.57 प्रतिशत रह गई.

दिल्ली में इमारत गिरने पर मनोज झा की दो टूक, 'मुझे पता था कि...'

दिल्ली : दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना पर एक तरफ सरकार एक्शन ले रही है तो दूसरी ओर सियासत भी तेज है. आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने इस पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि यह पहला हादसा नहीं है और हम हादसों का इंतजार करते हैं. सांसद मनोज झा ने कहा, ''हम हादसों के इंतजार में प्रतिक्षारत देश बन चुके हैं. पहले नहीं हुआ था क्या? क्या हासिल हुआ? मुझे पता था कि एक छोटे स्तर के अधिकारी को नाप कर बड़े लोग सुरक्षित रहेंगे... छात्रों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई, हॉस्टल कहां हैं? सार्वजनिक शिक्षा की इतिश्री कर दी है, उसकी कब्र बना दी है. वहां किसी की नजर नहीं है...''

विजय सिन्हा बोले- मुख्यमंत्री देख रहीं

दिल्ली में इमारत गिरने की घटना पर बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, ''यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. दिल्ली की मुख्यमंत्री पूरी गंभीरता के साथ इस मामले को देख भी रही हैं. कार्रवाई भी शुरू हो गई है. भविष्य में ऐसी घटना न घटे, उस पर भी वो लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं...''

अब तक 7 लोगों की हुई मौत

बता दें कि दिल्ली के सत्य निकेतन में बीते रविवार की दोपहर मरम्मत कार्य के दौरान एक इमारत ढह गई थी. सोमवार शाम तक की रिपोर्ट के अनुसार, मलबे से 12 लोगों को निकाला गया है. इनमें से सात की मौत हो गई है. सात में से छह मृतकों की पहचान हो चुकी है.

सत्य निकेतन में इमारत गिरने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक हरिराम, उनकी पत्नी उर्मिला और उनके बेटे महेश को गिरफ्तार कर लिया है. हरिराम को भिवाड़ी में पकड़ा गया है. कई अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं. दिल्ली में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है.

कानपुर: बहू ने करवाई थी हत्या... दवा कारोबारी मर्डर केस में खुलासा

कानपुर: उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने दवा कारोबारी हत्याकांड में सनसनीखेज और चौकाने वाला खुलासा किया है, पुलिस इस मामले में मृतक की बहू यानी बेटे की पत्नी को आरोपी बनाया है. पुलिस के अनुसार, बहू ने ही बदमाशों को बुलाकर अपने ससुर की हत्या करवाई थी, पुलिस ने बहू और हत्याकांड में शामिल बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: फॉरेंसिक रिपोर्ट से बढ़ सकती है आरोपियों की मुश्किलें, कोर्ट ने दी पूछताछ की अनुमति...

अयोध्या। राममंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जेल में निरुद्ध आठों आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस संबंध में आरोपियों का बयान पुनः दर्ज कराने के लिए सोमवार को विवेचक पुलिस क्षेत्राधिकारी ने विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा के समक्ष अर्जी दी थी। न्यायालय ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है। विवेचना के दौरान कथित तौर पर आरोपियों के कब्जे से बरामद की गई नगदी, सिक्के, आभूषण व अन्य सामग्रियों को फॉरेंसिक जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। इसकी रिपोर्ट पुलिस का प्राप्त हो गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में पुलिस ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट आरोपियों के विरुद्ध अहम साक्ष्य साबित हो सकते हैं। आरोपियों का बयान विवेचना को नई दिशा दे सकता है। इससे नए साक्ष्य सामने आ सकते हैं। इसी प्रकरण में आरोपियों को कुछ दिनों पूर्व झटका लगा था।

ऑस्ट्रिया के स्कूलों में हिजाब बैन लागू...

सरकार बोली- इस्लामिक देश नहीं बनने देंगे, भड़के इस्लामिक संगठन

वियना: ऑस्ट्रिया में 14 साल से कम उम्र की लडकियों के लिए स्कूलों में हिजाब और बुर्का पहनने पर रोक लगाने वाला कानून लागू हो गया है। यह कानून देश भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ''पारंपरिक मुस्लिम'' सिर ढकने वाले कपडों, जैसे हिजाब या बुर्का, पर रोक लगाता है।

ऑस्ट्रिया में हिजाब पर प्रतिबंध वाला कानून पहले ही पास कर दिया गया था, लेकिन उसे लागू अब किया गया है। इस कानून का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है और अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया है। वहीं, ऑस्ट्रियाई सरकार ने इसे दमन की निशानी करार दिया है। ऑस्ट्रिया की चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने इस कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि वह ऑस्ट्रिया को इस्लामिक देश नहीं बनने देंगे। ऑस्ट्रिया की इंटीग्रेशन मिनिस्टर क्लाउडिया बाउर का कहना है कि हिजाब ''दमन की निशानी है और बचपन से ही लड़कियों पर नियंत्रण रखने का एक जरिया है।'' यह कानून तीन मध्यमार्गी पार्टियों - कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी, सोशल डेमोक्रेट्स और लिबरल नियोस - के कंजर्वेटिव-नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने प्रस्तुत किया था। उनका कहना है कि यह कानून जेंडर इक्वालिटी (लैंगिक समानता) के प्रति सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि इसका मकसद युवा लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करना है। वहीं, आलोचकों का कहना है कि हिजाब पर प्रतिबंध का नया कानून

देश में मुसलमानों के खिलाफ भावनाएं भड़का रहा है और यह असंवैधानिक हो सकता है।

ऑस्ट्रिया में आधिकारिक इस्लामिक कम्युनिटी की कार्ला अमीना बगहाजाती ने इस प्रतिबंध का कड़ा विरोध किया है। ''हमारा मानना है कि यह धर्म की आजादी के मौलिक अधिकार को अनुचित रूप से सीमित करता है और मुस्लिम लड़कियों पर बहुत ज्यादा असर डालता है।'' ऑस्ट्रियाई सरकार ने कहा है कि शिक्षकों से उम्मीद की जाती है कि अगर वे किसी बच्चे को हिजाब या बुर्का पहने हुए देखते हैं, तो वे छात्र और उनके कानूनी अभिभावकों के साथ बातचीत करके नए बैन को लागू करवाएंगे। अगर बार-बार नियमों का उल्लंघन होता है, तो चाइल्ड सर्विसेज को सूचित किया जाना चाहिए और आखिरी उपाय के तौर पर, अभिभावकों पर €800 (87789 रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

ईरान-ओमान का समझौता ट्रंप को देगा झटका, होर्मुज स्ट्रेट में अब क्या होगा?

ईरान : पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और तनाव के बीच अब ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कुछ ऐसा करने की तैयारी में जुटा है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है. दरअसल, ईरान ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए एक नए शिपिंग कॉरिडोर की स्थापना से जुड़े समझौते पर साइन हो जाएंगे. हालांकि, देश के टॉप सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि अमेरिका के हमले और अन्य विरोधी गतिविधियों के रुकने तक ईरान इस रणनीतिक जलमार्ग को पूरी तरह से फिर से खोलने की कोई गारंटी नहीं देगा.

ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रेजाई ने रविवार (6 सितंबर, 2026) को सरकारी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, 'ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए एक अस्थायी शिपिंग कॉरिडोर की व्यवस्था को लेकर बातचीत कर रहे हैं. इस रूट के कुछ हिस्से ईरान और ओमान के जलक्षेत्र से होकर गुजरेंगे और प्रस्तावित कॉरिडोर से जहाजों के आने और जाने का मैनेजमेंट तेहरान करेगा.' उन्होंने कहा, 'यह बातचीत उस जलमार्ग पर मैरीटाइम ट्रैफिक बहाल करने के कूटनीतिक कोशिशों का हिस्सा है, जिसके जरिए युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया का करीब पांचवें हिस्से का तेल और लिक्विफाइड नैचुरल गैस की शिपिंग होती थी.'

होर्मुज स्ट्रेट तभी खुलेगा, जब वर हमलों से दूर होगा- रेजाई

मोहसिन रेजाई ने कहा, 'तेहरान तभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुले रहने की गारंटी देगा, जब अमेरिका हमलों और उन गतिविधियों से दूर रहेगा, जिसे ईरान नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई मानता है. युद्ध खत्म करने और व्यापक समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने के मकसद से जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन में सबसे बड़ी दिक्कत गारंटी का न होना था और मध्यस्थ भी इसके इंप्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने में नाकाम रहे.'

रूस में हिमस्खलन की चपेट में आए पर्वतारोही, अब तक 11 की मौत, 6 लापता

रूस : रूस के नॉर्थ कौकशस के काबार्डिनो-बालकारिया इलाके में एक हिमस्खलन की चपेट में पर्वतारोहियों के एक समूह के आने से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है. इसके साथ ही, छह अन्य लोग लापता हो गए हैं. यह हिमस्खलन रविवार (6 सितंबर, 2026) को स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 5 बजे रूस के सबसे ऊंची चोटियों में से एक माउंट मिजिरगी पर आया. स्थानीय इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक, पर्वतारोहियों की समूह में कुल 33 लोग शामिल थे, जिसमें से सोमवार (7 सितंबर, 2026) को सुबह 9 बजे तक 10 पर्वतारोही खुद ही पहाड़ के नीचे उतर आए थे,

जबकि बाकी छह अन्य पर्वतारोहियों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका था. स्थानीय इमरजेंसी सर्विसेज की टीम ने बताया कि इस घटना के बाद पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. इस ऑपरेशन में इमरजेंसी टीम के 50 से ज्यादा लोग जुटे हुए थे. हालांकि, उन्होंने कहा कि दुर्गम इलाकों और फिर से हिमस्खलन होने के बढ़ते खतरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल आ रही थी.

मॉस्को: रूस और चीन ने बना दिया महा रिकॉर्ड...

पुतिन-जिनपिंग दोस्ती हुई और मजबूत

मॉस्को: रूस और चीन ने वो कर दिखाया है,जो भारत अब तक नहीं कर सका है। दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार पिछले तीन दशकों में 30 गुना से ज्यादा बढ़कर 200 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। वहीं, भारत-रूस व्यापार अब भी 70 बिलियन डॉलर पर अटका हुआ है, जिसमें तेल की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। भारत और रूस द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। हालांकि, चीन-रूस व्यापार अभी लगभग तीन गुना ज्यादा आगे निकल चुका है, जो दोनों देशों को और ज्यादा करीब ला रहा है। यही कारण है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबंध भी मजबूत हुए हैं।

रोसनेफ्ट के सीईओ इगोर सेचिन ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के दौरान रूस-चीन एनर्जी बिजनेस फोरम में कहा कि रूस और चीन मिलकर दुनिया के कुल एनर्जी प्रोडक्शन का एक-तिहाई हिस्सा पैदा करते हैं, और पिछले 30 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार 50 गुना

से ज्यादा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता के बीच ''नॉर्दर्न सी रूट'' एक अहम एनर्जी कॉरिडोर बनता जा रहा है, जिसमें चीन को प्राथमिकता मिल रही है। रूस-चीन के बीच लेन-देन अब लगभग पूरी तरह से रूबल और युआन में होता है, जिससे पश्चिमी करेंसी पर निर्भरता कम हुई है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस और चीन मिलकर दुनिया के कुल एनर्जी प्रोडक्शन का लगभग एक-तिहाई हिस्सा पैदा करते हैं, जबकि पिछले साल चीन की एनर्जी खपत अमेरिका और यूरोप की कुल खपत से 40% ज्यादा थी। चीन के कोयला आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 20% है, और रूस चीन के न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए एनरिच्ड यूरेनियम का मुख्य सप्लायर भी है। रूस चीन का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है और चीन के तेल आयात में उसकी हिस्सेदारी लगभग 23% है। साथ ही, रूस से बेहतर तरीके से तेल खरीदने से बीजिंग को $27 बिलियन से ज्यादा का आर्थिक फायदा हुआ है।

भारत-रूस व्यापार

भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल 2026 में 70 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था और 2026 की पहली छमाही में इसमें फिर से जबरदस्त तेजी आई है।

ग्लोबल इंपैक्ट फोरम में सुनील शेट्टी कल्चरल आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित

मुंबईः मुंबई में आयोजित ग्लोबल इंपैक्ट फोरम (जीआईएफ) एडिशन 2 की गाला नाइट में बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी को कल्चरल आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एपी ग्लोबले की डायरेक्टर जाह्ववी पवार द्वारा यह सम्मान प्राप्त करने पर खुशी जताते हुए सुनील शेट्टी ने इसे अपने दर्शकों के लंबे समय से मिल रहे प्यार का नतीजा बताया और आयोजकों का धन्यवाद किया।

इस फोरम के पहले दिन भारत-ब्राजील और भारत-चीन के बीच लय, नृत्य, खेल, मार्शल आर्ट्स और पारंपरिक कलाओं के सांस्कृतिक आदान-प्रदान के जरिए सभ्यतागत विरासत का जश्न मनाया गया। साथ ही कार्यक्रम में कई दिग्गजों का भी आना हुआ। वहीं जाह्ववी पवार ने जोर देकर कहा कि सच्ची वैश्विक एकता राजनीति और अर्थशास्त्र से परे साझा संस्कृति, खेल और पारंपरिक ज्ञान को अपनाने से ही संभव है। यह गाला नाइट इस बात का प्रतीक बनी कि जब पुरानी विरासत को नई पीढ़ी द्वारा साझा और आगे बढ़ाया जाता है, तभी उसे सही मायने में समकालीन अर्थ मिलता है।

'काम के लिए एक्टर-प्रोड्यूसर संग!'

मुंबई : टीवी की चर्चित अभिनेत्री प्रियंका पंडित अब रेहाना पंडित के नाम से जानी जाती हैं। निजी जिंदगी में उतार-चढ़ाव झेल चुकीं रेहाना ने हाल ही में अपनी जिंदगी के कई कड़वे किस्सों पर खुलकर बात की। पति की बेवफाई और करियर ब्रेक के बाद अब उन्होंने खुद पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का भी करारा जवाब दिया। दरअसल, रियलिटी शो में आजमा फलाह ने रेहाना पर आरोप लगाते हुए विवादित टिप्पणी की थी कि वह काम पाने के लिए एक्टर-प्रोड्यूसर के साथ सोती हैं। इस पर रेहाना ने कहा कि आजमा उन्हें जानती तक नहीं थीं और जानबूझकर ऐसी बात कही गई, ताकि वह भड़क जाएं। रेहाना ने बताया कि उस वक्त जीशान उनके बॉयफ्रेंड थे और आजमा शायद उन्हें ट्रिगर करना चाहती थीं। लेकिन रेहाना ने पलटवार करने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। उनका कहना था कि जब बात सच नहीं है, तो गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं।

'४० की उम्र में २० जैसी शेप चाहिए!' बिपाशा ने ट्रोलर्स को दिखाया आईना

मुंबई : बेटी को जन्म देने के बाद बढ़े वजन को लेकर ट्रोलिंग झेल रहीं बिपाशा बसु ने अब बॉडी शेमिंग करने वालों को करारा जवाब दिया है।

बातचीत में अभिनेत्री ने कहा कि महिलाओं से आज भी शरीर को लेकर अवास्तविक उम्मीदें की जाती हैं।

उनके मुताबिक, बच्चा होने के बाद भी महिलाओं से ऐसी उम्मीद रहती है कि वे ४० की उम्र में २० साल जैसी फिटनेस तुरंत वापस पा लें।

बिपाशा ने कहा कि जब कोई महिला जल्दी शेप में नहीं लौटती तो सोशल मीडिया ट्रोलर्स बेरहम हो जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ पैपराजी ने उनकी बेहद अजीब तस्वीरें खींचीं और उनके संघर्ष को समझने की कोशिश नहीं की।

हालांकि, बिपाशा ने साफ कर दिया कि ट्रोलिंग उन्हें तोड़ नहीं सकती। उनका कहना है कि उन्हें अपने सफर, जिम्मेदारियों और लक्ष्य का पता है और वह दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपनी राह नहीं बदलेंगी।

मचेगा 'घमासान', होगी 'द रिवोल्यूशनरीज' की क्रांति, 40 भूतों से भी सामना, 10 फिल्मे और वेब सीरीज

मुंबईः सिनेमाघरों में 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' ने धूम मचा रखी है।

जबकि शुक्रवार, 11 सितंबर को बड़े पर्दे पर अक्षय कुमार और सैफ अली खान की 'हैवान', मनोज बाजपेयी की 'लास्ट मैन इन टावर' रिलीज होने वाली है। लेकिन यदि आप उन दर्शकों में से हैं, जो घर बैठे मनोरंजन का भरपेट लुत्फ उठाना चाहते हैं तो फिक्र मत कीजिए।

OTT पर सितंबर के इस नए हफ्ते में आपके लिए 10 नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं।

खास बात यह है कि इस बार तीन की तीन हिंदी रिलीज बिल्कुल ओरिजनल ओटीटी रिलीज हैं।

डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया क्राइम-थ्रलिर 'घमासान' लेकर आ रहे हैं, जिसमें डाकू बने अरशद वारसी और पुलिस अधकिारी बने प्रतीक गांधी आमने-सामने हैं।

इसके साथ ही निखलि आडवाणी आजादी से पहले के दौर की क्रांतिकारी गाथा 'द रिवोल्यूशनरीज' सीरीज ला रहे हैं।

इसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा लीड रोल में हैं। हॉरर और सुपरनैचुरल थ्रिलर पसंद करते हैं तो आपके लिए 'अली बाबा और 40 भूत' रिलीज हो रही है, जो एक न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट और एक पुलिस अधिकारी की कहानी है। इसकी कहानी एक लापता पिता की तलाश से शुरू होती है और 40 बेचैन भूतों के रहस्य में उलझ जाती है।

साउथ इंडस्ट्री के पिटारे से एक मजेदार मलयालम सीरीज 'प्रिंस ऑफ मॉलीवुड' रिलीज हो रही है, जिसे आप हिंदी डब वर्जन में भी देख सकते हैं।

रोकठोक लेखनी खबरें वे-रोकटोक
मुंबई : बुधवार 09 सितंबर 2026 से 15 सितंबर 2026

महिम में नशे के खिलाफ जागरूकता की जरूरत...

सबरी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने उठाई आवाज

मुंबईः नशीले पदार्थों का बढ़ता खतरा समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है विशेष रूप से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए केवल कानूनी कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगातार जनजागरूकता, परिवारों की भागीदारी और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग की भी आवश्यकता है। मुंबई के महिम क्षेत्र में भी युवाओं, विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों के बीच नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। समय रहते युवाओं को सही मार्गदर्शन और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराया जाए तो उन्हें नशे की गिरफ्त में जाने से बचाने में मदद मिल सकती है।

पुलिस और सामाजिक संस्थाओं के बीच समन्वय जरूरी

सबरी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष फैसल शेख ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन के साथ सामाजिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों को मिलकर काम करना चाहिए।

फैसल शेख ने कहा कि महिम पुलिस और मुंबई पुलिस की विभिन्न शाखाओं के साथ सामाजिक स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित कर युवाओं और परिवारों तक नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल नशे के नुकसान के बारे में बताना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें शिक्षा, खेल, रोजगार, कौशल विकास और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना भी जरूरी है, ताकि उनके सामने सकारात्मक भविष्य के अवसर मौजूद रहें।

महिम से मुंबई के दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचे संदेश

महिम मुंबई का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहां विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। ऐसे क्षेत्र में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान का व्यापक सामाजिक प्रभाव हो सकता है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, अभिभावकों के साथ संवाद, युवाओं के लिए खेलकूद एवं सामाजिक गतिविधियां और स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता

बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। महिम के साथ दादर, धारावी और आसपास के क्षेत्रों में भी इस प्रकार के प्रयासों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

दूसरे शहरों और राज्यों में भी जागरूकता की जरूरत

नशीले पदार्थों की समस्या केवल मुंबई या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी युवाओं को नशे से बचाने के लिए सरकारी विभागों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जागरूकता के प्रयास किए जाते हैं। इन प्रयासों से सीख लेकर मुंबई में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अधिक प्रभावी जनजागरूकता कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। खासकर युवाओं और विद्यार्थियों तक सही जानकारी पहुंचाना इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।

परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण

नशे से बचाव में परिवार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। माता-पिता को बच्चों के व्यवहार और उनके मित्रों की संगति पर ध्यान देने के साथ-साथ उनके साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए। यदि किसी युवा में नशे से जुड़ी समस्या दिखाई देती है तो उसे केवल डांटने या सामाजिक रूप से अलग करने के बजाय उचित मार्गदर्शन और सहायता दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए।

युवाओं को सकारात्मक दिशा देना जरूरी

सबरी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष फैसल शेख ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान का उद्देश्य युवाओं को डराना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा दिखाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को युवाओं के लिए शिक्षा, खेल, रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने होंगे। पुलिस प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं मिलकर नियमित जागरूकता अभियान चलाएं तो नशे के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया जा सकता है।

महिम से उठे नशामुक्त समाज का संदेश

महिम से नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश मुंबई के अन्य क्षेत्रों और देश के दूसरे शहरों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए पुलिस, सामाजिक संस्थाओं, विद्यालयों, परिवारों और आम नागरिकों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जागरूकता, संवाद, सहयोग और सही मार्गदर्शन के माध्यम से ही युवाओं को नशे से दूर रखकर बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाया जा सकता है।

मनोज जरांगे की चेतावनी !

‘मुंबई में एक भी युवक का खून बहा तो...’

मुंबई : मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे के अनशन का आज (07 सितंबर) दसवां दिन है. इस बीच जरांगे ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर ढिलाई और लापरवाही बरत रही है, जिससे मराठा समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. उन्होंने सरकार को 12 सितंबर तक का समय दिया है. उन्होंने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुंबई में एक भी युवक का खून बहा तो 10 मिनट के भीतर महाराष्ट्र बंद हो जाना चाहिए. जरांगे ने उस दिन सभी मराठा समाज के लोगों से अंतरवाली सराटी पहुंचने की अपील की है.

मनोज जरांगे ने कहा, ‘‘सरकार जानबूझकर ढिलाई और लापरवाही कर रही है. मराठा समाज का आक्रोश बढ़ रहा है. मराठा समाज को खत्म करने के लिए जानबूझकर लापरवाही की जा रही है. हमने सरकार को 12 तारीख तक का समय दिया है. सभी मंत्रियों ने कहा था कि आपको अनशन करने की नौबत नहीं आएगी. मार्च और फरवरी में प्रसाद लाड ने कहा था कि हमें बुलाइए. उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस मराठों की मांगें पूरी करेंगे. इसलिए लाड को बुलाया गया था, लेकिन एक साल में उन्होंने कुछ नहीं किया.’’

जरांगे ने आगे कहा, ‘‘एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की यह मिलीभगत है. हमें जानकारी मिली है कि शिंदे के दो मंत्री और दो प्रवक्ता आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. मुंबई की ओर निकलने के बाद हमला कर फडणवीस को बदनाम करने की सरकार की साजिश है. बावनकुले और उनके लोगों की भी यही गतिविधियां चल रही हैं. पिछले दो-तीन दिनों में कुछ पत्रकारों से सलाह ली जा रही है कि आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए.

मुंबईः समुद्र का बढ़ता स्तर मुंबई के लिए कितना खतरनाक सामने आई चिंता

मुंबईः देश की आर्थिक राजधानी और सपनों की नगरी कही जाने वाली मुंबई पर जलवायु परिवर्तन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्र का बढ़ता जलस्तर, जमीन का धंसना, भारी बारिश और ऊंची समुद्री लहरें भविष्य में शहर के निचले इलाकों के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट में मुंबई समेत दक्षिण एशिया के कई तटीय शहरों को समुद्र के बढ़ते जलस्तर से खतरे को लेकर आगाह किया गया है। इसके बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने शहर के लिए नया क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट शुरू कराया है।

इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी मुंबई अचानक समुद्र में समा जाएगी। वैज्ञानिक चेतावनी मुख्य रूप से लंबे समय में समुद्र के बढ़ते स्तर से निचले तटीय इलाकों में स्थायी जलभराव, बार-बार बाढ़ और लोगों के विस्थापन के बढ़ते जोखिम को लेकर है। 2100 तक कितना बढ़ सकता है समुद्र का स्तर? संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में वैश्विक औसत समुद्र स्तर में रिकॉर्ड 5.9 मिलीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने के बावजूद इस सदी के आखिर यानी 2100 तक वैश्विक समुद्र स्तर कम से कम करीब आधा मीटर बढ़ सकता है।

वहीं बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों और पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की चादर में अस्थिरता जैसे कारकों के कारण वृद्धि दो मीटर तक पहुंचने की आशंका वाले परिदृश्य भी मौजूद हैं। मुंबई जैसे समुद्र किनारे बसे घनी आबादी वाले शहर के लिए यह खतरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मुंबई को ज्यादा खतरा क्यों? मुंबई की भौगोलिक स्थिति इस संकट को और गंभीर बनाती है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर 4 ए, फ्लोर-जीआरडी, 29 डी, शबन हाउस, वंजावाडी लेन, माहिम वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400016 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhani.com